उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 07 अक्टूबर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(10/39)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को परेड ग्राउण्ड में हिमान्या सरस मेला–2017 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने 18 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों, हस्तशिल्पियों एवं स्वरोजगारियों द्वारा लगाये गये विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मेलों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों के स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। विभिन्न राज्यों के उद्यमियों द्वारा लगाये गये अलग–अलग स्टॉलों से अनेक राज्यों के उत्पादों और उनके मार्केटिंग के बारे में जानकारी एक साथ प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने, सबको आवास, शौचालय एवं 01 मई 2018 तक प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सबको सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों का विकास करना एवं सेल्फ मार्केटिंग करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष बल देना होगा। प्राकृतिक उत्पादों का उत्तराखण्ड में अच्छा कारोबार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह, विधायक श्री खजान दास, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के अध्यक्ष श्री एस.एस.नेगी, श्री सुनील उनियाल, श्री उमेश अग्रवाल, ग्राम्य विकास के अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत आदि उपस्थित थे।

*सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।*

**देहरादून 07 अक्टूबर, 2017(सू.ब्यूरो)** **प्रेस नोट–03(10/38)**

सरकार ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दीपावली से पहले राज्य की सभी शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सचिव, वित्त श्री अमित सिंह नेगी द्वारा सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के लिए 278 करोड़ 90 लाख 93 हजार रूपये की धनराशि का शासनादेश जारी किया गया है। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के तहत सभी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों के साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए जारी की गई है।

प्रदेश के 6 नगर निगमों यथा हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, काशीपुर व देहरादून के लिए 58 करोड़ 60 लाख 17 हजार रुपये की धनराशी जारी की गयी है। इस राशि से निगम स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि, पथ प्रकाश व जल संस्थान के बकायों और रिटायर कर्मचारियों के दावों का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा अवशेष धनराशि से केवल सफाई व स्वच्छता संबंधी वाहन जैसे कूड़ा वाहन, डंपर, टिप्पर, जेसीबी, कम्पेक्टर वाहन की भी खरीद की जा सकती है, लेकिन स्वच्छता वाहन के अलावा इस राशि से अन्य वाहन जैसे जीप और स्टाफ कार नहीं खरीद सकेंगे।

प्रदेश के 40 नगर पालिका परिषदों के लिए उक्त शर्तों के साथ ही 69 करोड़ 39 लाख 33 हजार की धनराशि एवं 14 नगर पंचायतों के लिए 9 करोड़ 15 लाख 97 हजार की धनराशि जारी की गई है। निदेशक, शहरी विकास के कर्मचारियों की पेंशन निधि के लिए 1 करोड़ 4 लाख 18 हजार रुपए दिए गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए त्रैमासिक किस्त के तहत कुज 121 करोड़ 85 लाख 28 हजार की धनराशि जारी की गई है। इसमें से 13 जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 86 हजार की धनराशि जारी की गई है। 95 क्षेत्र पंचायतों के लिए दूसरी छमाही किस्त के रूप में 36 करोड़ 55 लाख 58 हजार रूपये, 7953 ग्राम पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रूपये की धनराशि जारी की गई है।

नई बनी दो नगर पालिकाओं के लिए 1 करोड़ 25 लाख, 26 नई नगर पंचायतों के लिए 16 करोड़ 25 लाख, गैर निर्वाचित निकायों के लिए 1 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है। इस तरह से शहरी स्थानीय निकायों को कुल 157 करोड़ 5 लाख 65 हजार रुपए की धनराशि जारी की गई है।

***सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।***

**डोईवाला/देहरादून 07 अक्टूबर, 2017(सू.ब्यूरो)** **प्रेस नोट–02(10/37)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शनिवार को पब्लिक इंटर कॉलेज, डोईवाला में 'डोईवाला विज्ञान मेला' के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आशा व्यक्त की कि विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विज्ञान मेले छात्र–छात्राओं के बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजकों नेशनल काउन्सिल फॉर साईंस एण्ड टैक्नॉलोजी कम्यूनिकेशन, सोसाईटी पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन साईंटिस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड स्टेट काउन्सिल फॉर साईंस एंड टैक्नॉलोजी और जस्ट ओपन योरसैल्फ सोसाईटी, देहरादून के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों के परम्परागत ज्ञान को मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने विद्यालयों के अनुरोध पर विद्यार्थियों को प्रादेशिक विज्ञान केन्द्र में भ्रमण हेतु अनुमति दिये जाने की बात भी कही।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विद्यालयों की हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय आए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने विज्ञान प्रदर्शनी में संस्थानों द्वारा लगाए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया।

***सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।***

**कोटद्वार/देहरादून 07 अक्टूबर, 2017(सू.ब्यूरो)** **प्रेस नोट–01(10/36)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कोटद्वार के सिटी मांटेसरी स्कूल में आयोजित जनता–मिलन कार्यक्रम में आम जन की विभिन्न समस्याओं को सुना व उनके त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनता मिलन में अधिकतर समस्याएं आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क व मुआवजे से संबंधित थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कोटद्वार स्थित स्टेडियम का नाम स्व. सचिदानंद भारती के नाम पर रखने, विकास खण्ड दुगड्डा में विभिन्न स्थानों यथा 4 किमी, 1.5 किमी तथा 2.5 किमी सीसी मार्ग के निर्माण करने, स्व.चन्द्रमोहन अस्पताल से कलालघाटी के बीच 90 मीटर डबल लेन पुल तथा बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सिम्भलचौड़–सिताबपुर तथा हल्दूखाता–दुर्गापुर के 12 कि.मी. मोटर मार्ग निर्माण भी किया जायेगा।

जनता–मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। सभी न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रारम्भिक चरण में 50 न्याय पंचायतों से यह शुरूआत की जायेगी, जिससे महिलाओं एवं युवाओं हेतु रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय पार्कों में विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों की तैनाती की गई है साथ ही आर्मी से भी डॉक्टरों की मांग की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सकें। इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पं.दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत लघु, सीमान्त एवं गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार द्वार 2 प्रतिशत की ब्याज दर पर 01 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कृषि तथा बागवानी के माध्यम से स्वरोजगार को अपनाये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी को बढ़ावा देने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके तहत पंचुर, खैरा तथा लखोली गांव में चकबंदी कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा सीमांत क्षेत्रों में अखरोट के 4 हजार पौध भी निःशुल्क वितरित की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री व विधायक कोटद्वार डॉ.हरक सिंह रावत, विधायक श्री महंत दलीप रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, जिलाधिकारी श्री सुशील कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जे.आर.जोशी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।

*नोट : जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।*